	States Region	1985 AESG CES Report	1989 Report	% variation over 1985 GOI	1993 Report	% variation over 1989
	N. E. INDIA					——
7.	Arunachal Pradesh		3150		2500	-20.63%
8.	Assam (incl. Nagaland)		3500		5500	+57.14%
9.	Meghalaya		3287		2750	-16.33%
10.	West Bengal		155		200	+29.03%
1.	Tripura		135			N.A.
	TOTAL	10468	12227	+16.80%	10950	-10.44%
	N. W. INDIA					
2.	Uttar Pradesh	445	525	+ 17.97%	875	+66.67%
	TOTAL	445	525	+17.97%	875	+66.67%
	GRAND TOTAL:	18960	21687	+14.38%	25571	+17.91%

मध्य प्रदेश में सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का दुरुपयोग

4081. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:**
श्री राघवजी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में उन गैर सरकारी सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं के नाम क्या है जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया गया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक संस्था को प्रत्येक वर्ष किस-किस प्रयोजन के लिये कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ग) इनमें से उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मंत्रालय को उन्हें प्रदान की गई राशि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी; और

(घ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान इस संबंध में लागू की गई नई प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सीधे किसी गैर सरकारी सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है। इन संस्थानों के उद्देश्य शैक्षिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासात्मक कार्यकलाप इत्यादि हो सकते है। ऐसी संस्थाओं के नामों का केन्द्रीय रूप से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, सामान्यतः विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में एक लाख रु० और उससे अधिक के अनुदानों का ब्यौरा होता है जिसे संसद में माननीय सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान की सिफारिशें

4082. **श्री गोविन्दराव मिरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में भारत में कृषि उत्पादन में लगातार गिरावट पर अपनी चिन्ता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो अगली शताब्दी के दौरान खाद्यान्नों की मांग और आपूर्ति के संबंध में क्या-क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट "इण्डियन एग्रीकल्चर इमर्जिंग परस्पेक्टिव एंड पालिसी इशूज" (दिसम्बर 1994 अंक) में भारत में कृषि उपज में लगातार आने वाली कमी के बारे में उल्लेख नहीं किया है। उसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत में खाद्यान्नों के लिए घरेलू मांग में कमी आई है जो कि मूलरूप से गैर-खाद्यान्न वस्तुओं की व्यापक किस्मों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग करने के कारण हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

में लगातार आने वाली कमी के बारे में उल्लेख नहीं किया है। उसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत में खाद्यान्नों के लिए घरेलू मांग में कमी आई है जो कि मूलरूप से गैर-खाद्यान्न वस्तुओं की व्यापक किस्मों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग करने के कारण हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Measures for Large scale seed Multiplication

4083. DR. MOHAN BABU:
SHRI YERRA NARAYANASWAMY:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the measures taken for large scale seed multiplication to ensure farmers' protection to enhance productivity and lessen the dependence on foreign seed companies; and

(b) by when the Draft Plant Varieties Law is proposed to be introduced to enable the farmers to free themselves from foreign seed companies?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) For large scale multiplication and distribution of quality seed to farmers there is a well established infrastructure which includes the National Seeds Corporation, the State Farms corporation of India, the State Seed Corporations, the State Government Seed Farms and a large number of private sector seed companies. The National Seeds Project has contributed substantially in improving seed production and processing infrastructure as well as seed quality control. Quality seed production is also encouraged through various central sector and centrally sponsored schemes for crop development and seed production/ distribution.

(b) The draft legislation for protection of plant varieties is under finalisation in consultation with various Ministries/ Departments. The legislation will be introduced after completion of due procedures required in the matter.

रेलवे कल्याण और राहत कोष के अंतर्गत लाभ भोगी

4084. श्री अजीत जोगी:
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान रेल कर्मियों और उनके परिवारों को रेल मंत्री कल्याण एवं राहत कोष से कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ख) इस सहायता के प्रदान किये जाने के लिये क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज):

(क) 1994-95 — 62,000/- रुपये
1995-96 — 6,09,000/- रुपये

(ख) विपत्तियों यथा प्राकृतिक विपदाओं, लम्बी बीमारी, अचानक मृत्यु आदि में रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए इस कोष से सहायता मुहैया करायी जाती है।

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान रेल मंत्री कल्याण और राहत कोष से 15 रेल कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा, उत्तर रेलवे के बाढ़ पीड़ित कर्मचारियों को सामूहिक राहत के रूप में उत्तर रेलवे को 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों को अध्ययन अवकाश देने संबंधी प्रावधान

4085. श्री पराग खालिहा:
श्री शिव चरण सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों के उच्च अध्ययन हेतु वेतन सहित अध्ययन अवकाश का अधिनियमन करने संबंधी कोई प्रावधान है;